स्वागत योग्य कदम : भारत की जी20 की अध्यक्षता

शैलेंद्र कुमार[1] एवं संजीव राज [2]

जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत को सभी देशों को अपने दृष्टिकोण के अनुरूप साथ लाने की जरूरत होगी

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा कमान सौंपे जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 की प्रक्रिया का नेतृत्व संभाल लिया, जोकि भारत को सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच आम सहमति बनाने की स्थिति में लाएगा। पहली दिसंबर से शुरू होने वाली अध्यक्षता की यह जिम्मेदारी भारत के जिम्मे ऐसे समय में आई है जब दुनिया आर्थिक तंगी और वैश्विक मंदी से जूझ रही है। इसके अलावा, अमेरिका , यूरोपीय संघ, और रूस जैसे जी20 के सदस्य देशों के बीच के राजनीतिक ध्रुवीकरण के मद्देनजर भारत की मेजबानी में होने वाली हर बैठक तनाव से भरी होगी। लेकिन बाली में संपन्न हुए जी20 शिखर सदस्य देशों द्वारा एक संयुक्त बयान देने में विफल रहने की आशंका के बीच प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल के शेरपा 17-पृष्ठों वाले आम सहमति के दस्तावेज़ को पूर्ण करने में कामयाब रहे। उम्मीद के मुताबिक, रूस-यूक्रेन संघर्ष से संबंधित अनुच्छेद को लेकर समस्या हुई। वार्ता के दौरान कुछ भाषा को संयमित करने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला गया और सितंबर में शंघाई कॉ-ऑपरेशन आर्गनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में दिए गए श्री मोदी के "यह युद्ध का युग नहीं है" वाले मुहावरे को अंतिम वक्तव्य में शामिल कर लिया गया। जैसा कि भारत और कुछ अन्य देश करते रहे हैं, जी20 नेतृत्व का बहुमत इस संघर्ष के मसले पर गोलमोल बात कहने के पक्ष में नहीं था। संयुक्त विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि "अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में

[1] वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
[2] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , नई दिल्ली

युद्ध की कड़ी निंदा की"। यह एक सकारात्मक संकेत रहा कि रूस ने यद्यपि इस बयान का विरोध किया, लेकिन उसके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस शिखर सम्मेलन में मौजूद रहे। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन की गैरमौजूदगी ने इंडोनेशिया के लिए इस शिखर सम्मेलन के प्रबंधन को आसान बनाने में योगदान दिया।

श्री मोदी द्वारा भोज के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ भी अपना हाथ बढ़ाने का तथ्य सितंबर में एससीओ शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं द्वारा दिखाए गए सख्त आचरण के उलट है और यह 2020 में एलएसी गतिरोध शुरू होने के बाद पहली बार उनके बीच खटास दूर होने का संकेत हो सकता है। श्री मोदी को घरेलू मोर्चे पर भले ही इस बदलाव की कैफियत देनी पड़ सकती है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति से बात करने का उनका निर्णय इस व्यावहारिक हकीकत को भी दर्शाता है कि 2023 में जी20 और एससीओ के मेजबान के रूप में भारत के लिए उन समूहों, जिसमें चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी शामिल हैं, की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी होगा। लगभग 200 बैठकों की योजना के साथ जी20 की अध्यक्षता वाले वर्ष में भारत को इस किस्म की और अधिक व्यावहारिकता की जरूरत होगी। इस मकसद को हासिल करने के लिए नई दिल्ली को इस फोरम के भविष्य की खातिर सभी देशों को अपने दृष्टिकोण के अनुरूप साथ लाना होगा और इस मुश्किल दौर में दुनिया के आर्थिक नेतृत्व को आगे बढ़ाना होगा और जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग, खाद्य एवं ऊर्जा संकट, आतंकवाद एवं संघर्ष और डिजिटल विभाजन को पाटने सहित भविष्य के खतरों की तैयारी करनी होगी।

भारत की G20 प्रेसीडेंसी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

जी20 की भारत की अध्यक्षता को घरेलू परिदृश्य पर अपने वैश्विक सपनों को पूरा करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। सरकार द्वारा 1 दिसंबर को कुछ धूमधाम के साथ जी-20 प्रेसीडेंसी का अपना वर्ष शुरू किया और भारत के जी20 लोगो जो "वसुधैव कुटुंबकम, या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के आदर्श वाक्य का प्रतीक है के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक 100 स्मारकों को दीप्तमय कर यादगार बनाया गया। "एक संपादकीय निबंध में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता के वर्ष को एक ऐसा वर्ष बनाने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की है, जो हमारी 'एक पृथ्वी' को ठीक करने, हमारे 'एक परिवार' के भीतर सद्भाव बनाने और हमारे 'एक भविष्य' की उम्मीद देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पूरे भारत में लगभग 200 जी20 बैठकें आयोजित करने की योजना है। प्रारंभिक और मंत्रिस्तरीय बैठकें जी20 शिखर सम्मेलन के भव्य योजनाओं के अंग हैं और यह सितंबर 2023 माह में 'पी-5' देशों और अन्य के नेताओं को नई दिल्ली में आमंत्रित करेगी।

भारत ने इंडोनेशिया से अपनी अध्यक्षता प्राप्त की है, जिसमें यूक्रेन युद्ध पर मतभेदों के कारण बैठकों के आयोजन और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय कठिन था। अंत तक भी अनिश्चितता थी कि क्या सभी प्रमुख नेता भाग लेंगे? क्या वे एक संयुक्त फोटो अवसर के लिए सहमत होंगे? और क्या एक संयुक्त बयान होगा। क्या इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो की तरह, श्री मोदी को यह सुनिश्चित करने के लिए विदेश यात्रा करनी होगी कि सभी जी20 नेता और आमंत्रिती उच्चतम स्तर पर भाग लें और अधिकारियों को बयानों पर आम सहमति प्राप्त करने के लिए आधी रात जागना होगा।

प्रतीकवाद और तार्किक समन्वय एक तरफ सरकार के पास एक व्यापक जी20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए ठोस बातचीत करने का एक कठिन कार्य है। अधिकारियों के अनुसार वे आतंकवाद, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और वैश्विक एकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वर्ष 2008 में, अमेरिका में पहली जी20 शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठक दुनिया की वित्तीय प्रणालियों के सबसे बड़े संकट दौर में आयोजित की गई थी। वर्ष 2022 में, यह अध्यक्षता का कार्य पीएम श्री मोदी और उनकी टीम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में रूसी युद्ध के स्थायी प्रभावों को देखते हुए, इस समय और गहरे हो रहे ऊर्जा पर पश्चिमी प्रतिबंध, आर्थिक मंदी, महामारी की चिंता, और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे, वैश्वीकरण की नींव और एक परस्पर जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के विषय बेहद अहम हैं। अपने संपादकीय में, श्री मोदी ने कहा कि भारत सामूहिक निर्णय लेने की अपनी परंपरा के माध्यम से अपना जी-20 एजेंडा बनाएगा, जो कि भारत की राष्ट्रीय सहमति की तरह, लाखों मुक्त आवाजों को एक सामंजस्यपूर्ण राग प्रदान करेगा। एक समय में भारत स्वयं आर्थिक संकट, सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव का सामना कर रहा था। आज मन की बात के माध्यम से पीएम मोदी द्वारा भारत के लिए G20 की अध्यक्षता वैश्विक भलाई पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर है, को स्वीकारा गया है। जी20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की वैश्विक प्रमुखता और वैश्विक परिकथा को आकार देने की अपनी शक्ति को बढ़ाने के बाद, बड़ी जिम्मेदारी का एहसास है। इससे अपने वैश्विक सपनों को घरेलू परिदृश्य में बदलने की क्षमता के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त, G20 के अध्यक्ष के रूप में यूक्रेन की कुछ अनुकूल स्थितियों को भारत स्वीकार करता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ के देशों के साथ मिलकर संघर्ष के समाधान की दिशा में काम करने के लिए मानवहित में स्वयं की जिम्मेवारी भी मानता है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जी20 के भावों को व्यक्त करना अपने आप में

भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक पटल पर सुदृढ़ता के साथ रखता है।

भारत की जी20 अध्यक्षता एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। इसलिए हमारा विषय है – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"। जी20 की पिछली 17 अध्यक्षताओं ने महत्वपूर्ण परिणाम दिए – व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने, देशों पर ऋण-बोझ से राहत देने सहित कई अन्य परिणाम। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे और उनसे आगे का निर्माण करेंगे।

हालाँकि, जैसा कि भारत ने यह महत्वपूर्ण दायित्व ग्रहण किया है, मैं अपने आप से पूछता हूँ – क्या जी20 अभी भी आगे बढ़ सकता है, क्या हम संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए मानसिकता में मौलिक बदलाव ला सकते हैं, ... और मेरा मानना है कि हम कर सकते हैं।

हमारी मानसिकता हमारी परिस्थितियों से आकार लेती है। पूरे इतिहास में, मानवता अभाव में जी रही थी। हमने सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष किया, क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन्हें उपलब्ध न कराने पर निर्भर था। विचारों, विचारधाराओं और पहचानों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा आदर्श बन गई। दुर्भाग्य से, हम आज भी उसी मानसिकता में फंसे हुए हैं। हम इसे तब देखते हैं जब देश, क्षेत्र या संसाधनों को लेकर लड़ते हैं। हम इसे तब देखते हैं जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बना दिया जाता है। हम इसे तब देखते हैं जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है, जबकि अरबों लोग असुरक्षित बने रहते हैं।

कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि टकराव और लालच केवल मानव स्वभाव है। मैं असहमत हूं। यदि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होते, तो इतनी सारी आध्यात्मिक परंपराओं की स्थायी अपील, जो हम सभी की मौलिक एकता की वकालत करती है, की क्या व्याख्या होती।

ऐसी ही एक परंपरा, जो भारत में लोकप्रिय है, सभी जीवित प्राणियों और यहां तक कि निर्जीव चीजों को भी उन्हीं पांच मूल तत्वों - पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के पंच तत्व से बना देखती है। इन तत्वों के बीच सामंजस्य - हमारे भीतर और हमारे बीच - हमारे शारीरिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण के लिए आवश्यक है। आज, हमारे पास दुनिया के सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के साधन हैं। आज, हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है - हमारे युग को युद्ध का युग बनने की ज़रूरत नहीं है।

आज, समाज की बड़ी चुनौतियों- जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी को एक-दूसरे से संघर्ष से नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करके ही हल किया जा सकता है। सौभाग्य से, आज की तकनीक हमें मानवता-व्यापी स्तर पर समस्याओं का समाधान करने के साधन भी प्रदान करती है। आज हम जिस विशाल आभासी दुनिया में रहते हैं वह डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मापनीयता को प्रदर्शित करता है। मानवता का छठा हिस्सा निवास करने वाला और अपनी भाषाओं, धर्मों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं की विशाल विविधता के साथ, भारत दुनिया का एक सूक्ष्म जगत है।

सामूहिक निर्णय लेने की सबसे पुरानी ज्ञात परंपराओं के साथ, भारत लोकतंत्र के मूलभूत डीएनए में योगदान देता है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी आदेश से नहीं, बल्कि लाखों स्वतंत्र आवाज़ों को एक सुर में मिलाने से बनती है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल हमारे प्रतिभाशाली युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा का पोषण करते हुए, हमारे हाशिए पर रहने वाले नागरिकों का भी ख्याल रखता है। हमने राष्ट्रीय विकास को ऊपर से नीचे तक शासन करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिक-नेतृत्व वाला 'जन आंदोलन' बनाने का प्रयास किया है। हमने डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है जो खुली, समावेशी और अंतर-संचालित हैं। इनसे सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे विविध क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति हुई है। इन सभी कारणों से, भारत के अनुभव संभावित वैश्विक समाधानों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

अपनी जी20 अध्यक्षता के दौरान, हम भारत के अनुभवों, सीखों और मॉडलों को दूसरों, विशेषकर विकासशील दुनिया के लिए संभावित टेम्पलेट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। हमारी जी20 प्राथमिकताएँ न केवल हमारे जी20 भागीदारों, बल्कि वैश्विक दक्षिण में हमारे अन्य देशों के परामर्श से भी तय की जाएंगी, जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। हमारी प्राथमिकताएँ हमारी 'एक पृथ्वी' को ठीक करने, हमारे 'एक परिवार' के भीतर सद्भाव पैदा करने और हमारे 'एक भविष्य' के लिए आशा देने पर केंद्रित होंगी। अपने ग्रह को स्वस्थ बनाने के लिए, हम प्रकृति के प्रति भारत की ट्रस्टीशिप की परंपरा के आधार पर टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करेंगे।मानव परिवार के भीतर सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए, हम भोजन, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति का अराजनीतिकरण करने का प्रयास करेंगे, ताकि भू-राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बने। हमारे अपने परिवारों की तरह, जिनकी ज़रूरतें सबसे बड़ी हैं, उनके बारे में हमेशा हमारी पहली चिंता होनी चाहिए।

अपनी भावी पीढ़ियों में आशा का संचार करने के लिए, हम सबसे शक्तिशाली देशों के बीच सामूहिक विनाश के हथियारों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर एक ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहित करेंगे। भारत का जी20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्य-उन्मुख और निर्णायक होगा। आइए हम भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को उपचार, सद्भाव और आशा की प्रेसीडेंसी बनाने के लिए मिलकर काम करें। आइए हम मानव-केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को आकार देने के लिए मिलकर काम करें।

भारत के लिए जी20 की अध्यक्षता निश्चित रूप से देश को वैश्विक पटल पर एक सशक्त और सक्षम नेतृत्वकर्ता के रूप में खड़ा करता है। आने वाले दौर में इसके आर्थिक, राजनैतिक परिणाम भारत के हित में होते दिखाई पड़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर, 2022 को नुसा दुआ, बाली, इंडोनेशिया में जी20 शिखर सम्मेलन में जी20 प्रेसीडेंसी हैंडओवर समारोह के दौरान गैवेल धारण करते हुए। फोटो साभार: एपी